



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 1980/फाल्गुन 22, 1901

No. 45]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 1980/PHALGUNA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त संचालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

बजट अनुभाग

बजट 1980-81

वित्त मंत्री का भाषण

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1980

पृष्ठ सं० वि० सं० (डीईए) मू० प्रो० सं० 15(1)-बी (डी०)/80—

महोदय

मैं, वर्ष 1980-81 का अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।

2. भारत की जनता से हमारी पार्टी को जो विशाल जनदेश मिला है वह स्तब्धता, सामाजिक और आर्थिक विकास के उन बहुत से कार्यक्रमों को फिर से नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का जनदेश है जिन्हें हमने हमने 1977 से पहले प्रारम्भ किया था, किन्तु जो जनता-लोकदल शासन के तेसीस महीनों के दौरान छिन्न-भिन्न हो गए थे। 1977 में हमने जो सुबुद्ध और संक्षम अर्थव्यवस्था छोड़ी थी उसे और आगे बढ़ाने की बजाय उन्होंने अपनी निष्क्रियता और कुप्रबन्ध के द्वारा गतिरुद्ध कर दिया। इस स्थिति को सुधारने एवं तेजी से आर्थिक विकास के लिए अथक परिश्रम करने, गरीबी हटाने और सामाजिक असमानताओं को दूर करने तथा 20-सूची कार्यक्रम पर अमल करने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। किन्तु, तेसीस महीने के जनता-लोकदल शासन के बाद जो अर्थव्यवस्था

हमें विरासत में मिली है वह ऐसी है कि उसकी क्षति का जायजा लेने और उसमें फिर से नई जान डालने तथा उसे सही स्थिति में लाने के उद्देश्य से एक सुसंगत मध्यमकालिक नीति तैयार करने के लिए हमें कुछ और समय की जरूरत होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम मध्यकालिक गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए तब तक कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाएंगे जब तक कि एक संगत मध्यमकालिक नीति नहीं बन जाती। अपने भाषण में मैं आगे चल कर संक्षेप में उन बहुत से उपायों की रूपरेखा बनाऊंगा जो हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने और उसमें फिर से भरोसा पैदा करने के लिए पिछले आठ सप्ताहों में किए हैं। जाहिर है कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने हमें जो अघोषित पथ दिखाया है उस पर अपने देश को आगे ले जाने के लिए बहुत से अन्य उपाय करने की जरूरत है। इस समन्वित कार्यक्रम की रूपरेखा में अवगत होने के लिए मैं, सबन से कुछ सप्ताह के बाद 1980-81 का निगमित बजट प्रस्तुत किये जाने तक प्रतीक्षा करने का अनुगोच करूंगा।

3. अंतरिम बजट और अनुदानों की मांगें जो सम्मानित सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं उनमें पहले से स्वीकृत व्यय को ही प्रायः जारी रखा गया है और कुछ थोड़े से परिवर्तन किये गए हैं जो अनिवार्य थे। वे पर्याप्त रूप से वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के द्योतक नहीं हैं क्योंकि हमने जब से शासन भार संभाला है, हमें इन्हें तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। हम यह महसूस करते हैं कि पिछली सरकार ने जो योजना तैयार की थी वह उन नीतियों और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो हमने अपने चुनाव

चोरणा-पत्र में शामिल किए थे और जिनके आधार पर हमें विशाल जनोद्धार मिथा है। इसलिए हमें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि योजना आयोग का पुनर्गठन नहीं हो जाता और वह 1980-81 की प्राथमिकताओं और योजना-परिचयों को अन्तिम रूप नहीं दे देता। जब यह ये निर्णय ले लिये जाएंगे तब मैं फिर एक व्यापक कार्यक्रम लेकर गहन के सामने उपस्थित होऊंगा।

4. चालू वर्ष में आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। वर्ष 1979-80 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1 से 2 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। कृषि उत्पादन में 6 प्रतिशत के घासपास कमी होने की आशंका है और औद्योगिक उत्पादन में प्रगति की वर पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ी-सी कम या उतनी ही रहेगी। विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट और उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि की दर अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। चालू वित्तीय वर्ष में कीमतें लगभग 20 प्रतिशत बढ़ी हैं। खासतौर पर आम उपभोग की चीजों, जैसे चीनी, गूड़, खादमारी, आलू, प्याज तथा खाद्य तेलों की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। कीमतों पर यह दबाव जितना देश में पूर्ति संबंधी कठिनाइयों के कारण है उतना ही बजट के भारी घाटे के कारण भी है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण और देश में कम उत्पादन होने की वजह से इस्पात और सीमेंट जैसी वस्तुओं का अधिक आयात किये जाने के कारण व्यापारिक घाटा (रैप) पहले की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी ओर, स्पष्ट नीति न होने के कारण भी निर्यात में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है।

5. वर्ष 1979-80 के दौरान आर्थिक स्थिति में जो गिरावट आई है उसके लिए पिछले खरीफ के मौसम में पड़े सूखे को बहाना बनाना असमान होगा। यह सच है कि चालू मौसम में देश के बहुत बड़े भाग में भयंकर सूखा पड़ा। लेकिन उसके बारे में हमारा विचार यह है कि हमारी पार्टियों द्वारा मातृवंत दशक के आखिरी वर्षों में जो नई कृषि नीति शुरू की गई थी उस पर अमल कर के मौसम के उतार-चढ़ाव के असर को कम किया जा सकता था। यदि बिजली का उत्पादन अधिक होता और धीज, उर्वरक, डीजल आदि की पूर्ति की व्यवस्था अधिक प्रभावशाली होती तो पिछले खरीफ के मौसम में उत्पादन में जिस तरह की कमी आई थी उसके कुप्रभाव से अर्थव्यवस्था को काफी हद तक बचाया जा सकता था। यदि कोई सरकार, पिछली जनता सरकार की तरह, 1977-78 और 1978-79 में मिली अच्छी सफलता के लिए श्रेय लेती है तो उसमें यही प्रकट होता है कि वह केवल अच्छे मौसम पर ही निर्भर रहती है और उसके पास कोई फलदायक नीति नहीं है। और जब सूखे के रूप में उस सरकार की पहली परीक्षा हुई तो उसकी नीति का दिवालियापन सामने आ गया और वह आम जनता को उबारने में बुरी तरह असफल रही। उस समय जिस व्यवस्था ने उनका और देश की गरीब जनता का उद्धार किया, वह थी खरीद और सार्वजनिक वितरण की प्रणाली जो हमारी पार्टियों ने बनाई थी और जिसके अन्तर्गत हमने अनाज का विशाल भंडार उनके लिए छोड़ा था। हमें पिछली सरकार के प्रति अवश्य आभारी होना चाहिए क्योंकि उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह नष्ट-भ्रष्ट न करके कुछ रूपा की है।

6. इस समय आधारभूत क्षेत्रों में जो संकट की स्थिति व्याप्त है उससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले तीन वर्षों में अर्थ-व्यवस्था का प्रबन्ध किनता खराब रहा है। हमारी पार्टियों की सरकार ने पहले जो निर्णय लिये थे उनके फलस्वरूप यद्यपि विद्युत उत्पादन की क्षमता में हर वर्ष भारी वृद्धि होती रही है तथापि घटिया प्रबन्ध, कानून और व्यवस्था की समस्याओं और बिगड़े हुए औद्योगिक सम्बन्धों के कारण इस अतिरिक्त क्षमता से उत्पादन नहीं बढ़ सका। यदि सरकार आवश्यक संकल्प और कल्पना-शक्ति का परिचय देती तो ये सब कठिनाइयां हल की जा सकती थीं। पिछले चार सालों में कोयले का उत्पादन वस्तुतः गतिरुद्ध हो गया। दूसरी ओर रेलवे के यातायात की मात्रा भी लगातार

घटती गई है। हमें यह अशोभन वृत्त देखना पड़ रहा है कि विद्युत प्राधिकारी अपनी कमियों के लिए जहां एक ओर रेलवे और कोयला प्राधिकारियों को दोष दे रहे हैं वहां दूसरी ओर रेलवे तथा कोयला प्राधिकारी अपनी घमफलताओं के लिए विद्युत प्राधिकारियों को और आपस में एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। यदि इस तिराशाभक्त रिवाज की तुलना उससे पहले के वर्षों की सफलताओं से की जाए तो यह अपने आप समझ में आएगा कि एक प्रभावोत्पादक नीति से किनता कुछ प्राप्त किया जा सकता है।

7. मैंने पिछले तीन वर्षों के घटनाचक्र का उल्लेख इस उद्देश्य से नहीं किया है कि मैं किसी को दोष दूं या किसी पर लांछन लगाऊं, लेकिन इसमें मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहा है कि मैं आप लोगों को उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूरी तरह अवगत करा दूं जिसके परिप्रेक्ष्य में हमारी वर्तमान समस्याओं को देखा जाना चाहिए। जाहिर है कि यह समय परस्पर दोषारोपण करने का नहीं है। वास्तविक चुनौती तो यह है कि देश के सामने इस समय जो गंभीर समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए एक सक्षम राष्ट्रीय मतैक्य तैयार किया जाए। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में हम सदन के सभी वर्गों से सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर सदन को अवगत करना चाहता हूं कि हम वर्तमान गंभीर आर्थिक संकट से किस प्रकार निपटने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब से हमने कार्यभार संभाला है, तब से हम कोयला, विद्युत, पत्तन और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों के कार्य में सुधार करने के लिए सृजकस्थित रूप से प्रयत्नशील हैं। औद्योगिक आधारभूत ढांचे से संबंधित संविमंडलीय समिति कुछ अल्पकालिक हल खोजने में सफल हुई है जिससे इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्य में सुधार होगा। तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले की पूर्ति की व्यवस्था को सुचारू बना दिया गया है और इससे अच्छे परिणाम निकलने शुरू हो गए हैं। पन-बिजली के उत्पादन में जो कमी हुई है उसे अधिक से अधिक मात्रा में पूरा करने के लिए तापीय संयंत्रों की क्षमता के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। रेलों भी अपने कार्य को पहले से अधिक तेजी से और अधिक कुशलता के साथ पूरा करने के लिए अपने को तैयार कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि हमने जो कदम उठाए हैं वे औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि करने, उपलब्ध क्षमताओं का उपयोग करने और कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में अवश्य ही प्रभावोत्पादक सिद्ध होंगे।

8. आधारभूत क्षेत्रों के कार्य के अलावा, सरकार कीमतों पर पड़ने वाले दबाव के कारण भी बहुत चिन्तित है। हमें उत्पादिकार में अत्यन्त विस्फोटक स्फीतिकारी अर्थव्यवस्था मिली है। बहुत-सी कठिनाइयों के बावजूद, अब वनस्पति-तेलों, किरोसीन और डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए और उनके समुचित वितरण की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए जोरदार कोशिशें की जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधिक प्रभावोत्पादक संचालन और जमाखोरी तथा काला-बाजारी की रोकथाम के लिए मुख्यस्थित प्रयत्नों के द्वारा हम कम मात्रा में मिलने वाली वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने वाले दबाव पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी, सीमेंट, कागज जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एक मध्यम-कालिक नीति तैयार की जा रही है। जब गैर-समान कीमतें बढ़ रही हों तो अपने देश में कीमतों को एक उचित स्तर पर स्थिर करना निस्संदेह कोई असमान काम नहीं है। फिर भी, सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने के लिए कृतसंकल्प है। राजकोपीय और मौद्रिक नीतियों का इस प्रकार बनाया जाएगा कि उनसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक निवेशों पर कोई कुप्रभाव डाले बिना, मुद्रास्फिति को नियंत्रित करने में सहायता मिले।

9. हालांकि अपना कार्यभार संभालने के बाद हमें जो सीमित समय मिला है उसमें हमारा ध्यान आवश्यकतावश अधिकतर तात्कालिक गंभीर

समस्याओं पर लगा रहा है, फिर भी हम अपने अभीष्ट सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और समन्वित नीति तैयार कर रहे हैं। चूंकि भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक कार्यापन को योजनाओं में कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के विकास को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही 1977 में हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में हमने एक कृषि विकास बैंक की शीघ्र स्थापना करने का वचन दिया था जो एक गरीब संस्था के रूप में हमारे किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मूल मदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस समय प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के संबंध में विधान का मसौदा तैयार करने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। हमारी सरकार ने ही फरवरी 1977 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह तय किया था कि वे अपने कुल अधिमां का कम से कम 33.3 प्रतिशत भाग कृषि, ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों को दें। इसी महानिर्णय के अन्तर्गत के दिनों में बैंक सरकारों क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों (चेयरमैन) के साथ मिल कर यह समीक्षा की थी कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकों को कहां तक सफलता मिली है और यह भी जर्नी की थी कि 20 सूची कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए बैंक क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। मुझे यह बताना हूँ खुशी हो रही है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अगले पांच वर्षों में अपने कुल अधिमां में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के हिस्से को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के दायित्व को स्वीकार कर लिया है। इससे ग्रामीण भारत के उत्पादक आधार को सुदृढ़ करने में बहुत अधिक गह्रायता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे और मीनान्तिक किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

1979-80 के संशोधित अनुमान

10. अब मैं संक्षेप में वर्ष 1979-80 के संशोधित अनुमानों की ओर आता हूँ।

11. वर्ष 1979-80 के बजट अनुमानों में 1382 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। पिछली सरकार द्वारा लिए गए कानिय निर्णयों के कारण और बजट के बाव की कुछ घटनाओं की वजह से चालू वर्ष में केन्द्र की बजट संबंधी स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, हमें 1300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूरक भागें समद के पिछले सत्र से प्रस्तुत करनी पड़ी थी। इसलिए मैं अतिरिक्त व्यय की विभिन्न मदों पर विस्तार से चर्चा करके मदन का समय नहीं लेता चाहूंगा। मैं यहां केवल उन थोड़ी सी मदों के बारे में ही बताऊंगा जिनमें खासतौर से वृद्धि हुई है।

12. चालू वर्ष में खास संबंधी आर्थिक सहायता पर 600 करोड़ रुपए यानी 540 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 40 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होगा; यह वृद्धि मुख्य रूप से गेहूं और धान की खरीद की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण हुई है।

13. आयानित उर्वरकों की लागत में वृद्धि, उर्वरक आयात की मात्रा में वृद्धि और उनको उठाने-धरने की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण, आयानित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता की राशि 144 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की अपेक्षा 176 करोड़ रुपए अधिक होगी। इसी प्रकार उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण, देशी उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता 304 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 19 करोड़ रुपए अधिक होगी।

14. चीनी निर्यातों पर होने वाली हानि सहित निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता के लिए बजट अनुमानों में 332 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी लेकिन अब इसमें 31 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी।

15. चालू वर्ष में रक्षा व्यय 3273 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है जबकि बजट में 3050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

16. राज्यों को दी जाने वाली आयोजना-भिन्न सहायता की राशि में इस वर्ष 120 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी पड़ी। जिसमें कि राज्य-द्वारा विचारित और सुझे के लिए राहत कार्यों के खर्च को पूरा कर सकें परन्तु बचतों के संग्रह के बदले राज्य सरकारों को दिए जाने वाले उधार का राजि भी 400 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में 225 करोड़ रुपए अधिक होगी।

17. बजट के बाद जो और घटनाएं घटी उनमें एक था बंगला देश को खाद्यान्न की पूर्ति जिस पर 29 करोड़ रुपए व्यय हुए और दूसरी थी लोक सेवा के आम चुनावों के संबंध में राज्य सरकारों को 30 करोड़ रुपए की 'लिखाया' अदायगी। इनके अलावा, महंगाई भत्ते के फार्मुले और पेंशन सम्बन्धी लाभों को उधार बनाने के लिए मार्च 1979 में जो निर्णय लिया गया उसके फलस्वरूप भी रक्षा, स्वास्थ्य और डाक-तार सार्वजनिक से सरकारों विभागों के खर्च में वृद्धि हो गई।

18. जहां तक आयोजना-अन्तर्गत का सम्बन्ध है, यह खेद का विषय है कि बहुत सी केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय आयोजना के लिए बजट समर्थन राशि में अनुमानित 332 करोड़ रुपए की कमी होगी। किन्तु काम के बढ़ते अन्तर्गत कार्यक्रम के लिए जो गई व्यवस्था में, चालू वर्ष के दौरान 300 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है क्योंकि प्रारम्भ में इस कार्यक्रम के लिए केवल 50 करोड़ रुपए की छॉटी सी व्यवस्था की गई थी और इसलिए केंद्रीय आयोजना के व्यय में 32 करोड़ रुपए की निबल कमी होगी।

19. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता में चालू वर्ष के दौरान 194 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी पड़ी। इस वृद्धि में से 125 करोड़ रुपए सूखा-प्रभावित राज्यों को अग्रिम आयोजना सहायता के रूप में देने के लिए है।

20. जहां तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है, अर्थ-व्यवस्था को असंतोषजनक प्रगति और आर्थिक वृद्धि की दर में सामान्य रूप में कमी आ जाने के कारण, चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय सरकार को निगम कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में 150 करोड़ रुपए की अत्यधिक कमी होने की संभावना है जबकि बजट में इस बार से 1630 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। उत्पाद शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसका बहुत कुछ कारण यह है कि पिछली सरकार ने कोयले पर जो उत्पाद शुल्क हटा दिया था और पेट्रोलियम उत्पादों के शुल्क की दर में कमी कर दी थी। अनुमान है कि चालू वर्ष में उत्पाद शुल्क में 6008 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 183 करोड़ रुपए की कमी रहेगी। किन्तु आयकर संग्रह और सीमा-शुल्कों की प्राप्तियों में 3636 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 498 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने की उम्मीद है। अनुमान है कि निबल कर-राजस्व में केन्द्र का हिस्सा 8020 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 199 करोड़ रुपए अधिक होगा।

21. आधारभूत ढांचे के लगभग बंद होने और आर्थिक तत्त्वों के प्रतिकूल हो जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कार्य पर बहुत बुरा असर पड़ा है। परिणामस्वरूप न केवल उनकी लाभार्जन क्षमता ही कम हो गई है बल्कि सरकार को ऋण की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी की वेतदारी को पूरा करने के लिए भी उनकी क्षमता को धक्का पहुंचा है। चालू वर्ष के दौरान इस खात में लगभग 260 करोड़ रुपए की कमी रहने की आशंका है।

22. कुछ विशेष सहायता-प्राप्त परियोजनाओं में भूगतान की गति धीमी होने के कारण और कुद्रेमुख परियोजना के लिए ईरानी प्राधिकारियों

से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में देरी हो जाने के कारण, चालू वर्ष के दौरान निवल विदेशी सहायता में 219 करोड़ रुपए की कमी रहने की संभावना है।

23. आयातित त्रूट और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण भी तेल उत्पादों के सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त होने वाला और उसके पास जमा होने वाला राशियाँ में 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमी हो गई है।

24. किन्तु कर-भित्त प्राप्तियों में जो कमी हुई है वह 1850 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 111 करोड़ रुपए के अधिक बाजार ऋणों के द्वारा और 650 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 925 करोड़ रुपए के अल्प बचन संग्रह के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई है।

25. उपर्युक्त और कुछ दूसरी घटबढ़ को हिसाब में लेने पर, अनुमान है कि इस वर्ष बजट में लगभग 2700 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

1980-81 का बजट अनुमान

26. अब मैं 1980-81 के अन्तरिम बजट प्रस्तावों के बारे में भी कुछ शब्द रहना चाहूँगा।

27. वर्ष 1980-81 के बजट में, जो कि इस समय 'लेखासुदान' के प्रयोजन से पेश किया जा रहा है, केन्द्रीय आयोजना के लिए 4600 करोड़ रुपए की समर्थन राशि रखी गई है। सरकार 'काम के बदले अनाज' की वर्तमान योजना को कुछ नया रूप देने के लिए विचार कर रही है ताकि उसे रोजगार बढ़ाने का एक अधिक समर्थ साधन बनाया जा सके। इसलिए, बजट में फिलहाल मौजूदा योजना के लिए केवल 70 करोड़ रुपए की ही व्यवस्था की जा रही है। इसे भी हिस्सा में शामिल करने के बाद, केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट में 4670 करोड़ रुपए का समर्थन दिया जाएगा जबकि वर्ष 1979-80 के बजट अनुमानों में इसके लिए 4411 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी।

28. केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट से बाहर के साधन धन वर्ष अनुमानित: 2003 करोड़ रुपए के होंगे जबकि चालू वर्ष के बजट में यह राशि 1604 करोड़ रुपए की थी। इस प्रकार अगले वर्ष के लिए कुल केन्द्रीय आयोजना परिस्य, चालू वर्ष के बजट में 6015 करोड़ रुपए की तुलना में 6573 करोड़ रुपए रखा गया है।

29. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाएं और 'ग्राम समायोजित कुल जनसंख्या' सूच के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता शामिल है, वर्ष 1979-80 के बजट में रखे गए 2697 करोड़ रुपए की तुलना में 2823 करोड़ रुपए की होगी। योजना आयोग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके, उनकी वर्ष 1980-81 की वार्षिक आयोजनाओं के लिए परिस्य निर्धारित कर दिए हैं। इन परिस्यों में उचित वृद्धियाँ की गई हैं जिससे कि विकास की गति को बनाए रखा जा सके। राज्यों ने योजना आयोग को आश्वासन दिया है कि वे साधनों को निर्धारित स्तर पर उपलब्ध रखेंगे और इन परिस्यों की वित्त-व्यवस्था करने के लिए प्रतिरिक्त साधन जुटाने के बारे में उन्होंने जो वचन दिए हैं उनका पालन करेंगे।

30. वर्ष 1980-81 में छात्र संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है यह उतनी ही राशि है जितनी कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में रखी गई है। जब तक कि देश में उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए आवश्यक आयात की मात्रा का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल जाता, तब तक आयातित और स्वदेशी उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि अगले वर्ष 600 करोड़ रुपए रखी गई है।

31. हम समय 3300 करोड़ रुपए के रक्षा व्यय का अनुमान लगाया गया है जबकि चालू वर्ष में यह राशि 3273 करोड़ रुपए की।

32. अन्य आयोजना-भित्त व्यय के लिए व्यवस्थाएं अत्यन्त मितव्ययता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई हैं।

33. करों की वर्तमान दरों पर कर-राजस्व में केन्द्र का हिस्सा अगले वर्ष अनुमानित: 8725 करोड़ रुपए का होगा जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में इसकी राशि 8219 करोड़ रुपए रखी गई है।

34. बाजार ऋणों से प्राप्तियाँ, चालू वर्ष के 1961 करोड़ रुपए के मुकाबले, अनुमानित: 2500 करोड़ रुपए की होंगी। अल्प बचतों से, चालू वर्ष के 925 करोड़ रुपए की तुलना में, अगले वर्ष 1000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वापसी अदायगी की रकमों को घटा कर, निवल विदेशी सहायता के रूप में 1196 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 918 करोड़ रुपए है।

35. अनुमान है कि वर्ष 1980-81 में केन्द्रीय सरकार की कुल प्राप्तियाँ 18980 करोड़ रुपए की होंगी। अगले वर्ष कुल व्यय 20215 करोड़ रुपए का होगा। इस प्रकार कराधान की मौजूदा दरों के अनुसार बजट में कुल मिला कर 1235 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

36. आज मैं एक वित्त विधेयक पेश करना चाहता हूँ जिसके द्वारा मौजूदा दरों की वित्तीय वर्ष 1980-81 में जारी रखने की अनुमति मांगी जाएगी। लेकिन मेरे पास आयकर अधिनियम में संशोधन के लिए तीन प्रस्ताव हैं जो विवादास्पद नहीं हैं। अब मैं संक्षेप में इन प्रस्तावों की व्याख्या करूँगा।

37. कुछ राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक हितों के संवर्धन के लिए कानूनी निगम स्थापित किए हैं। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के हितों के संवर्धन के लिए स्थापित, उन सभी कानूनी निगमों, निकायों, संस्थाओं या संगठनों की प्राय को, जो केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हों, आयकर से मुक्त कर दिया जाए।

38. जैसा कि सम्मानित सदस्यों का मासूम है, लद्दाख के लोगों को, उस जिले में या भारत से बाहर किसी भी क्षेत्र से प्राप्त या प्रोत्पन्न आय के संबंध में 1979-80 के कर-निर्धारण वर्ष तक जिसमें यह वर्ष शामिल है, आयकर की अदायगी में छूट दी गई थी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह छूट आगे तीन वर्ष तक और दी जाती रहे।

39. वर्तमान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक कार्य अथवा उपलब्धि के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुरस्कारों (प्रबाल) पर कोई आय कर नहीं लगता। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रकार की कर-रियायत गरीब, कमजोर और बीमार लोगों के कुछ-वर्ष को कम करने के उत्कृष्ट कार्य के लिए अनुमोदित पुरस्कारों पर भी लागू की जाए। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस व्यवस्था के कर दिए जाने से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मबर टेरेसा को दिए गए नोबल पुरस्कार की कराधेयता के बारे में जो सबेह उठ रहे हैं वे शान्त हो जाएंगे।

40. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। किन्तु वित्त विधेयक में 1980-81 के लिए मौजूदा दरों पर सहायक सीमा-शुल्कों और विशेष उत्पाद शुल्कों को जारी रखने की व्यवस्था की गई है।

41. महोदय, कुछ सप्ताह के बाद 1980-81 का नियमित बजट तैयार करने के सम्बन्ध में मैं, सदन से रजतारम्भ मुद्राव प्राप्त करने की प्रक्रिया करता हूँ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economics Affairs)

BUDGET DIVISION

BUDGET 1980-81

SPEECH OF MINISTER OF FINANCE

New Delhi, the 11th March, 1980

Sir,

I rise to present the Interim Budget for the year 1980-81.

2. The massive mandate that our Party has received from the people of India is clearly a mandate to pursue with renewed vigour various programmes for social and economic development initiated by us before 1977 but which were disrupted during the thirty-three months of the Janata-Lok Dal rule. Instead of building further the strong and resilient economy which we had left behind in 1977, they have allowed it to drift, through inaction and mismanagement, into stagnation. Our commitment to repair this damage, to work tirelessly for rapid economic development, for removal of poverty and social inequalities and for the implementation of the 20-point programme is firm and irrevocable. However, the state of the economy that we have inherited from the Janata-Lok Dal rule of thirty-three months is such that we shall need some more time to assess the damage suffered by the economy and to evolve a coherent medium-term strategy for revival and restoration of its health. This, of course, does not mean that we will not take effective steps to deal with the pressing short-term problems until such a consistent medium-term strategy has been evolved. Later in my speech, I shall outline briefly the various steps which our Government has taken in the last eight weeks to restore a measure of confidence and stability to the economy. Clearly, there is need to adopt many other measures to get our country moving again along the cherished path set out by Gandhiji and Jawahar Lal Nehru. For the outline of such an integrated approach, I plead with the House to wait until I come forward with the regular Budget for 1980-81 in a few weeks later.

3. The Interim Budget and the Demands for Grants being made available to Honourable Members reflect by and large the continuation of on going expenditure sanctioned earlier and certain minimum unavoidable changes. They do not reflect adequately the present Government's policies and programmes because since we took office we have not had enough time to formulate these. We feel that the Plan framed by the previous Government is inadequate to fulfil the policies and programmes set out by us in our election manifesto and on the basis of which we have received a massive mandate. We have therefore to wait till the priorities and plan outlays for 1980-81 are finalised by the Planning Commission to be appointed. I shall come to the House again with a comprehensive programme when these decisions have been taken.

4. In the current year the economic situation has deteriorated greatly. The year 1979-80 is likely to record a decline

of 1 to 2 per cent in Gross National Product. Agricultural production is expected to show a decline of something like 6 per cent and industrial production will be stagnant if not marginally lower than last year. The growth in key sectors like power, coal, steel, cement and fertilizers will be wholly inadequate to meet the needs of a growing economy. Prices have risen by about 20 per cent in the course of the current financial year. In particular, prices of some of the items of common consumption such as sugar, gur, khandasari, potatoes, onions and edible oils have recorded very sharp increases. This pressure on prices is as much due to domestic supply constraints as to a large budget deficit. The trade gap is going to be vastly larger because of the increase in prices of imports like petroleum and petroleum products and because of the larger imports of commodities like steel and cement due to poor domestic production. On the other hand, exports have not grown adequately because of lack of a clear policy.

5. It will be easy to make the drought in the last khariff season an excuse for the deterioration in the economic situation in 1979-80. It is true that the drought was serious in large parts of the country in the current season but one would have thought that the new agricultural strategy initiated by our Party in the late 1960s could have enabled the Government to minimise the impact of the fluctuations in weather conditions. Had power production been higher and had arrangements for supplying seeds, fertilizers, diesel etc., been more effective, it would have been possible to insulate the economy to much greater extent against the kind of decline in production that has occurred in the last khariff season. A Government which takes credit, as the previous Janata Government did, for the good performance in 1977-78 and 1978-79 merely underscores its dependence on good weather and its lack of effective policy instruments. And when the first test came in the form of a drought, the Government showed the bankruptcy of its policy and failed miserably to protect the common people. What has come to their rescue as well as to that of the poor people of the country has been the procurement and public distribution system that our Party had built up earlier and the large stocks of foodgrains that it had left to them. We must be thankful to the previous Government for the small mercy they had shown in not dismantling the public distribution system completely.

6. The mismanagement of the economy in the past three years can be seen most vividly in the crisis situation which prevails in the infrastructure sectors. Although large additions to power generating capacity have occurred year after year as a result of the decisions taken by our Party's Government earlier, the ability to generate power from this additional capacity has been very poor. Poor management, law and order problems, disturbed industrial relations—all of which could have been set right had the Government shown the necessary determination and imagination—have come in the way of higher production. Coal production has remained virtually stagnant for the last four years. Railways on the other hand have been carrying a continuously declining volume of traffic. We have had to witness the unedifying spectacle of the Power authorities blaming the Railways and Coal authorities for their deficiencies and these in turn blaming the Power authorities and each the other for their failures. This dismal record has only to be compared with the performance in the earlier years to realise what an effective policy can achieve.

7. I have referred to the developments in the past three years not with a view to apportion blame or trade accusations but merely to highlight the historical setting in which

our current problems have to be viewed. This is clearly not the time for indulging in mutual recriminations. The real challenge is to evolve a viable national consensus for solving the formidable problems now facing the country. In this vital national task, we seek the active co-operation of all sections of the House. I would like to take this opportunity to share with the House the manner in which we are tackling the present grave economic crisis. Since we assumed office, systematic efforts are being made to improve the functioning of vital infrastructure sectors such as coal, power, ports and Railways. A Cabinet Committee on Industrial Infrastructure has been able to identify some short-term solutions designed to improve the working of these vital sectors. Arrangements for supply of coal to thermal power plants have been streamlined and these are beginning to show positive results. Efforts are being made to improve the capacity utilisation of thermal plants so as to neutralise to the maximum extent the shortfall in the generation of hydro power. The Railways are gearing themselves to carrying out their tasks with greater speed and efficiency. I am confident that the measures which we have taken will have a favourable impact on the growth of industrial production, on the utilisation of available capacities and in moderating pressure on prices.

8. Apart from the functioning of infrastructure sectors, Government has been greatly worried about the pressure on prices. We have inherited a highly explosive inflationary economy. Despite several handicaps, vigorous efforts are now being made to augment supplies of essential commodities like vegetable oils, kerosene and diesel and to ensure their equitable distribution. Through a more effective functioning of public distribution system and systematic efforts to curb hoarding and blackmarketing, we are trying to contain the pressure on prices of commodities which are in short supply. A medium term strategy being evolved to encourage higher production of consumer goods like sugar, cement, paper, etc. In the background of world wide inflationary pressures, our task of stabilising domestic prices at a reasonable level is no doubt far from easy. However, Government is determined to use all available instruments to moderate pressure on prices of essential commodities. Fiscal and monetary policies will be so designed as to assist in control of inflation without affecting essential investments in key sectors of the economy.

9. While in the limited time we have had at our disposal since we assumed office our attention has of necessity been focussed largely on pressing immediate problems, we are beginning to evolve a comprehensive integrated strategy for achieving our cherished social and economic objectives. Since the bulk of Indian population lives in rural areas, development of agriculture and allied activities must receive high priority in our plans for social and economic transformation of our economy. It was in pursuit of this objective that our Party's election manifesto in 1977 had committed us to the early establishment of an Agricultural Development Bank as an apex institution for meeting the credit needs of our farmers. I am glad to report to the House that the Reserve Bank of India is now actively engaged in drafting the legislation of the proposed National Bank for Rural Development. It was again our Government which in February 1977 had set for the public sector banks a minimum target of 33.3 per cent of total advances going to the hitherto neglected sectors of agriculture, village and small industries. Earlier this month, I have reviewed with the Chairmen of public sector banks the performance of the banking system in achieving this target as well as the role that the banking system can play in accelerating the implementation of the

20-point programme. I am glad to report that public sector banks have agreed to accept the obligation of raising the share of priority sectors in their total lending to 40 per cent in the next five years. This will greatly help in strengthening the productive base of rural India. In meeting the credit needs of rural areas, priority attention will be given to requirements of small and marginal farmers and landless labourers.

Revised estimates for 1979-80

10. I now turn to a brief explanation of the Revised estimates for the year 1979-80.

11. A deficit of Rs. 1382 crores was estimated in the Budget for 1979-80. Certain decisions taken by the previous Government and other post-budget developments have severely affected the budgetary position of the Centre in the current year. As the Honourable Members are aware, supplementary demands involving additional expenditure of Rs. 1300 crores had to be presented in the last session of Parliament. I will, therefore not like to take the time of the House by dwelling at length on the various items of additional expenditure. I shall confine myself now only to certain major areas of increases.

12. Expenditure on food subsidy in the current year will be Rs. 600 crores i.e. Rs. 40 crores more than the Budget estimate of Rs. 560 crores—mainly due to increase in the procurement prices of wheat and paddy.

13. Owing to increase in the cost of imported fertilizers, increased volume of fertilizer imports and higher handling costs, the subsidy on imported fertilizers will be Rs. 176 crores more than the Budget estimate of Rs. 144 crores. Similarly, due to higher cost of production, the subsidy on indigenous fertilizers will be Rs. 19 crores more than the Budget estimate of Rs. 304 crores.

14. The provision for export subsidies including loss on sugar exports will be Rs. 31 crores more than the Budget estimate of Rs. 332 crores.

15. Defence expenditure in the current year is estimated at Rs. 3273 crores against the Budget provision of Rs. 3050 crores.

16. Non-Plan assistance to State Governments had to be stepped up in the current year by Rs. 120 crores to enable them to meet the expenditure on relief for natural calamities and drought. Loans to State Governments against net collections of small savings will also be Rs. 225 crores more than the Budget estimate of Rs. 400 crores.

17. Other post budget developments include supply of foodgrains to Bangladesh involving an expenditure of Rs. 29 crores, and 'on account' payment of Rs. 30 crores to State Governments in connection with the General Elections to Lok Sabha. Besides, the decisions taken in March 1979 for liberalisation of dearness allowance formula and pensionary benefits have also added to the expenditure of various Government departments, including Defence, Railways and Posts and Telegraphs.

18. So far as Plan expenditure is concerned, it is a matter of regret that the implementation of many of the Central Plan schemes has not been satisfactory. Consequently, the budgetary support for Central Plan is estimated to be less by as much as Rs. 332 crores. However, the provision for 'food for work' programme has been stepped up by Rs. 300 crores during the course of the year as a small provision of only Rs. 50 crores had been made for this programme initially, and consequently, the net shortfall in the Central Plan expenditure will be Rs. 32 crores.

19. The Central assistance for States' and Union Territories' Plans had to be stepped up by Rs. 194 crores during the current year. Of this increase, Rs. 125 crores is by way of advance Plan assistance to States affected by drought.

20. Coming to receipts, owing to poor performance of the economy and the general decline in economic growth, the revenues of Central Government from corporation tax in the current year are expected to register a sharp decline of Rs. 150 crores compared to the Budget estimate of Rs. 1530 crores. The revenues from Union excise duties have also been adversely affected largely by the decision of the previous Government to withdraw excise duty on coal and reduce the duties on petroleum products. The excise duties are estimated to register a shortfall of Rs. 183 crores in the current year compared to the Budget estimate of Rs. 6008 crores. However, collections of income-tax and receipts from customs duties are expected to yield Rs. 498 crores more than the Budget estimate of Rs. 3636 crores. Centre's share of net tax revenue is now estimated to be Rs. 199 crores more than the Budget estimate of Rs. 8020 crores.

21. The near collapse of infrastructure and the adverse economic factors have severely affected the working of various public sector undertakings. Consequently, not only their profitability has been eroded, but their capacity to meet their repayment and interest obligations to Government has also been undermined. A shortfall of nearly Rs. 260 crores on this account is anticipated in the current year.

22. The slow pace of disbursements in certain externally aided projects and delay in getting reimbursement for the Kudremukh Project from the Iranian authorities are likely to result in a shortfall of Rs. 219 crores in net external aid during the current year.

23. The increase in prices of imported crude and petroleum products has also led to erosion of the receipts and deposits with Government relating to oil products of over Rs. 300 crores.

24. These deteriorations in non-tax receipts have, however, been partially offset by a larger market borrowing of Rs. 111 crores over the Budget estimate of Rs. 1850 crores and estimated higher small savings collections of Rs. 925 crores as against the Budget estimate of Rs. 650 crores.

25. Taking these and other variations into account, the budgetary deficit in the current year is estimated to be about Rs. 2700 crores.

Budget Estimates for 1980-81

26. I shall now say a few words about the interim Budget for 1980-81.

27. In the Budget for 1980-81 which is now being presented for purposes of 'vote on account', budgetary support for Central Plan is placed at Rs. 4500 crores. Government is considering revamping of the present scheme of 'food for work' to make it a more potent instrument of employment generation. For the present, therefore, a provision of only Rs. 70 crores is being made in the Budget for the existing scheme. Taking this also into account, budgetary support for Central Plan will be Rs. 4570 crores against the Budget estimate of Rs. 4411 crores for the year 1979-80.

28. Extra budgetary resources for the Central Plan are estimated at Rs. 2003 crores next year as against Rs. 1604 crores in the current year's Budget. The total Central Plan outlay for next year is thus placed at Rs. 6573 crores as compared to Rs. 6015 crores in the current year's Budget.

29. Central assistance for States' and Union Territories' Plans, including the schemes of the Rural Electrification Corporation and assistance under 'Income Adjusted Total Population' formula, is placed at Rs. 2823 crores as against Rs. 2697 crores in the Budget for 1979-80. The Planning Commission has in consultation with the representatives of State Governments and Union Territories settled the outlays for their Annual Plans for the year 1980-81. A reasonable step-up in the outlays has been provided so that the tempo of development may be maintained. The States have assured the Planning Commission that they will keep the resources at the assessed level and adhere to the commitments made by them to mobilise additional resources to finance these outlays.

30. Provision for food subsidy in 1980-81 is Rs. 600 crores, i.e. at the same level as in the Revised estimate for the current year. Pending a clearer picture of the volume of imports needed to supplement domestic production, subsidy on imported and indigenous fertilizers next year is placed at Rs. 600 crores.

31. Defence expenditure is estimated at Rs. 3300 crores at this stage against Rs. 3273 crores in the current year.

32. Provisions for other non-Plan expenditure have been made keeping in view the need for utmost economy.

33. The Centre's share of tax revenues at existing rates of taxation is estimated at Rs. 8725 crores next year, as against Rs. 8219 crores in the Revised estimates for the current year.

34. Receipts from market borrowings are estimated at Rs. 2500 crores against Rs. 1961 crores in the current year. Small savings collections are estimated to fetch Rs. 1000 crores as against Rs. 925 crores in the current year. External assistance, net of repayments, is estimated at Rs. 1196 crores as against Rs. 918 crores in the Revised estimate of the current year.

35. The total receipts of the Central Government in the year 1980-81 are estimated at Rs. 18980 crores. The total expenditure in the next year will be Rs. 20215 crores. Overall budgetary gap at the existing rates of taxation will thus be Rs. 1235 crores.

36. I propose to introduce today a Finance Bill which seeks to continue the existing rates of income-tax for the financial year 1980-81. However, I have also three proposals of a non-controversial nature for the amendment of the Income-tax Act. I shall now briefly explain these proposals.

37. Some State Governments have set up statutory corporations for the promotion of socio-economic interests of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I propose to exempt from income-tax the income of all statutory corporations or bodies, associations or institutions wholly financed by the Central or a State Government, established for promoting the interests of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

38. As the Hon'ble Members are aware, residents of Ladakh were exempted from payment of income-tax upto and including the assessment year 1979-80 in respect of income accruing or arising to them from any source in that district or outside India. I propose to continue the tax exemption for a further period of three years.

39. Under the existing provisions, awards for literary, scientific and artistic work or attainment, instituted by the Central Government or by any State Government or approved

by the Central Government, are exempt from income-tax. I propose to extend this tax concession to approved awards for outstanding work in alleviation of the distress of the poor, the weak and the ailing. Hon'ble Members will be glad to know that this provision will set at rest doubts about the taxability of the Nobel Prize awarded to Mother Teresa in recognition of her service to suffering humanity.

40. There is no change in the rates of customs and Central excise duties. However, provision has been made in the Finance Bill for the continuance the auxiliary duties of customs and special duties of excise at the existing rates for the year 1980-81.

41. Sir, I look forward to constructive suggestions from the House for framing the regular Budget for 1980-81, a few weeks later.

A. C. TIWARI, Jt. Secy.